



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 629]

नई दिल्ली, बधवार, दिसम्बर 13, 1989/अग्रहायण 22, 1911

No. 629] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 13, 1989/AGRAHAYANA 22, 1911

इस भाग में शिन्न पछ संस्था वी जाती है जिससे ऐक यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation.

कार्यक्रम: सेवा-निवृत्ति और पेशन संग्रहालय
(कार्यक्रम और प्राप्तकालीन विभाग)

आवश्यकनाएँ
नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1989

सा. का. नि. 1046(श्री) —केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण
प्राप्तिक्रियम, 1985 (1985 की 13) की धारा 35 की उपधारा (2)
के खण्ड (ग) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग
करते हुए, एवं द्वारा हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष तथा
सदस्यों के बेतन तथा भत्ते और सेवा को शर्तें) नियमावली, 1986 में
योर्ज और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1 (1) इन नियमों का भाग हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों के बेतन तथा भत्ते और सेवा को शर्तें) संशोधन नियमावली, 1989 है।

2 (2) अधिकार रूप से जैरा अन्यथा उपनिधित है उसके सिवाय
वे नियम सरकारी राजनीत में इनके प्रयोग की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष तथा सदस्यों के
बेतन तथा भत्ते और सेवा को शर्तें) नियमावली, 1986 (जिसे इसके
बाद उक्त नियम कहा जाएगा), मे नियम 3 के परन्तुके चिह्न, निम्नलिखित

परन्तुके श्रेत्रस्थापित किया जाएगा—आरंभ जून, 1988 के प्रथम
दिन से प्रतिस्थापित किया जाया जाएगा अर्थात्—

“परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की प्रध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति
की स्थिति में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायालीय के रूप में
सेवा-निवृत्ति हुआ है या कोई उच्च न्यायालय के न्यायालीय के रूप में
सेवा-निवृत्ति हुआ है या जो पेशन और या उपदेश,
अभिदायी भविष्य निर्धारण में नियोजक के अधिकारों के रूप में कोई
सेवा-निवृत्ति कायदे या अन्य ब्राह्मण के सेवा-निवृत्ति कायदे प्राप्त
कर रहे हैं या करने का हक्कार हो गया है,
उसके बैतन में से उसके द्वारा प्राप्त पेशन अवधारी सेवा उपदान
के समतुल्य पेशन या अभिदायी भविष्य निर्धारण में नियोजक के अधिकार
दाय का किसी अन्य प्राप्त के सेवा-निवृत्ति कायदे, यदि कोई हो,
की कुल रकम कम कर दी जाएगी, परन्तु इनमें से उसके द्वारा प्राप्त
अवधारी प्राप्त किए जाने वाले सेवा-निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेशन
कम नहीं को जाएगी।”

3 उक्त नियमों के नियम 6 में—

(1) उप-नियम (1) के खण्ड (i) में “या उसका कोई भाग”
ये शब्द विलोपित कर दिए जाएं।

(2) उपनियम (3) में “180” संख्या के स्थान पर “240” संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी।

4. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (2) में, ‘या उसका कोई भाग’ ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 15 के बाद निम्नलिखित नियम जारी जाएगा, अवश्य—

“15क, उक्त नियमों के नियम 4 में 15 तक किसी बात के होने वाले भी, हिमाचल प्रदेश प्रगासनिक अधिकरण के अध्यक्ष की सेवा शर्तें तथा उन्हे उपरब्ध अन्य परिवर्धियां वही होंगी जो कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) प्रौढ़ उच्च न्यायालय न्यायाधीश (याका भत्ते) नियमावली, 1956 में उच्च न्यायालयों के सेवान्त न्यायाधीशों को अनुज्ञय की।”

[संख्या क-12018/2(i) 89-प्रश्ना अधि]

न्यायालयक ज्ञापन

केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश प्रगासनिक अधिकरण (प्रश्ना, तथा सदस्यों के बेतन तथा भत्ते और सेवा को शर्तें) नियमावली, 1986 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

2 यह प्रमाणित किया जाता है कि इन अधिसूचना का भवित्व लक्षी प्रमाण होगा, और इसका हिमाचल प्रदेश प्रगासनिक अधिकरण में पहले से ही कार्यरत किसी प्रग्राम, और सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी—ये मुद्रित नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 22 अगस्त, 1986 की सा. का. नि. संख्या 1015 (E) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(Department of Personnel & Training)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 13th December, 1989

G.S.R. 1046(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1.(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Amendment Rules, 1989.

(2) Save as otherwise expressly provided they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986

(hereinafter referred to as the said rules), for the proviso to rule 3, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of June, 1988, namely :—

“Provided that in the case of an appointment as a Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him.”

3. In rule 6 of the said rules, —

- (1) in clause (i) of sub-rule (1), the words “or a part thereof” shall be omitted;
- (2) in sub-rule (3), for the figures “180”, the figures “240” shall be substituted.

4. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (2), the words “or a part thereof” shall be omitted.

5. After rule 15 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely:—

“15A. Notwithstanding anything contained in rules 4 to 15 of the said rules, the conditions of service and other perquisites available to the Chairman of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and High Court Judge (Travelling Allowances) Rules, 1956.”

[No. A-12018/2(i)|89-AT]

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to amend the Himachal Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1986.

2. It is certified that this notification would have prospective effect and would not affect any Chairman, and Members of the Himachal Pradesh Administrative Tribunal already in position.

Footnote :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 1015(E) dt. the 22-8-86 in the Gazette of India.

मा. नि. 1047(ग्र) — केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) का धारा 35 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के गाय पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिवियों का प्रयोग करते हुए एनडब्ल्यूआर तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के बेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1988 में और आगे सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. (1) इन नियमों का नाम तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के बेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1988 है।

(2) अभिव्यक्ति स्वरूप सेवा अन्यथा उपबन्धित है, उसके नियम (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के बेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम सरकारी राजनीति में इसके प्रकाशन की तारीख की प्रवृत्त होती है।

2. तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के बेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 1988 (जिसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा), में नियम, 3 के परामुख के लिए, निम्नलिखित परामुख प्रतिनियोगित किया जाएगा और जून, 1988 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किया गया माना जाएगा, अर्थात् —

‘परामुख किसी भैमे अधिकार की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति की अधिकार के अधिकार के अध्यक्षाधीन के अधिकारों के रूप में सेवा-नियुक्ति हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से नियुक्त हुआ है या जो पेशन और या उपदान, अभिशायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिशाय के रूप में कोई सेवा-नियुक्ति फायदे या अन्य प्रकार के सेवा-रिवृति फायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका या प्राप्त करने का द्रक्कार हो गया है, उसके बेतन में से उसके द्वारा प्राप्त पेशन अथवा सेवा उपदान के समतुल्य पेशन या अभिशायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिशाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा-नियुक्ति फायदे, यदि कोई हो, की कुल रकम कम कर दी जाएगी, परन्तु इनमें से उसके द्वारा प्राप्त अथवा प्राप्त किए जाने वाले सेवा-नियुक्ति उपदान के समतुल्य पेशन कम नहीं की जाएगी।’

3. उक्त नियमों के नियम 6 में,—

(1) उप नियम (1) के खण्ड (i) में “या उसका कोई भाग” ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

(2) उप नियम (3) में “180” संख्या के स्थान पर “240” संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी।

4. उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (2) में, “या उसका कोई भाग” ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 15 के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात् —

“15A. उक्त नियमों के नियम 4 से 15 तक किसी बात के दौरान हुए भी तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की रोका गर्ते तथा उन्हें उत्तराध्यक्ष अन्य परिलक्षियां वही होंगी जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ते) नियमावली, 1956 में उच्च न्यायालयों के सेवारत न्यायाधीशों का अनुग्रह है।”

[म. क-12018/2(ii)/89 प्रशा. अधि.]

व्याख्यातक भाग

केन्द्रीय सरकार ने तमिलनाडु प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के बेतन तथा भत्ते और सेवा की शर्तें) नियमावली, 19 में सशोधन करने का निर्णय किया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इन अधिसूचना का अविष्य लंबी प्रमाण होगा और इसका नियमावली प्रशासनिक अधिकरण में पहले भैमे कार्यगत किसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर कार्य प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी — ये मुद्रण नियम भारत के राजनीति में दिनांक 29 जून, 1988 का गा. ला. नि. स. 756(६) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

G.S.R. 1047(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988; namely:—

1. (1) These rules may be called the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1989.

(2) Save as otherwise expressly provided they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988 (hereinafter referred to as the said rules), for the proviso to rule 3, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of June, 1988, namely :—

“Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him”.

3. In rule 6 of the said rules,—

(1) in clause (i) of sub-rule (1), the words “or a part thereof” shall be omitted;

(2) in sub-rule (3), for the figures “180”, the figures “240” shall be substituted.

4. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (2), the words “or a part thereof” shall be omitted.

5. After rule 15 of the said rules, the following shall be inserted, namely :—

“15A Notwithstanding anything contained in rules 4 to 15 of the said rules, the conditions of service and other perquisites avail-

able to the Chairman and Vice-Chairman of the Tamil Nadu Administrative Tribunal shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956."

[No. A-12018|2(ii)|89-AT]

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to amend the Tamil Nadu Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service in Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1988.

2. It is certified that this notification would have prospective effect and would not affect any Chairman, Vice-Chairman and Members of the Tamil Nadu Administrative Tribunal already in position.

Foot Note :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 756(E) dt. the 29-6-1988 in the Gazette of India.

सा. का. नि. 1014(अ) — नेत्रीय नरेकार प्रणासनिक अधिकारण अधिविनियोगम् 1985 (1985 का 12) की धारा 35 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत (ग) के माध्यम से उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेत्रीय अधिकार प्रणासनिक अधिकारण (अधिकार, उपाधिकार, तथा संस्थानों के) वैतन तथा भूमि और सेवों की शर्तें नियन्त्रित करते हैं और इसे संबोधन करते के लिए निम्नलिखित नियम अप्रतीत हैं, अर्थात् —

१. (१) इन नियमों का नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकारी (प्रशासन, उपाधान और सदस्यों के वेतन तथा भर्ते और सेवा कोषार्थ) संशोधन नियमावली, १९४९ है।

(2) अभियास स्वरूप से जैसा प्रथमांश उपर्यन्त है, उसके मिवायिं ये विद्यमान स्वरूपों गणपत में इनके प्रकारणत की ताँरीज़ी को प्रवत्त होते ।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (मध्यभा. उप.व्यवस्था तथा सदस्यों के बेस्त तथा 'भ्रम और सेवा की शिक्षा') नियमाभिनी, 1986 (जिसे इसके बाद उक्त नियम 'कहा जाएगा'), मेरे नियम 3 के प्रत्युक्त के लिए, निम्नलिखित प्रत्युक्त प्रतिव्यापित किया जाएगा जैर जैर, 1988 के प्रथम दिन से प्रतिव्यापित किया जाया जाना। अर्थात् — । । ।

“परन्तु किसी ऐसे अक्षित की अधिकत, उगाधियस ना सदम्य के रूप में निवृति की स्थिति में ‘जो त्रिमूर्ति’ उच्चल न्यायालय के न्यायालय के रूप में भी भेवा-निवृत्ति है। ही भी जो वैद्वत्यमें सर्वेक्षण था किसी राज्य मंदिरों के अर्थात् भेत्ता से निवृत्ति दुमा है या कि जो पेशन और या उपदान, अभिदायों भविष्य निधि में नियोजक के अभिदायक के रूप में काहि भेवा-निवृत्ति-फारद या अन्य प्रकार के भेवा-निवृत्ति कायदे प्राप्त कर रखा है वा कर त्वा है या प्राप्त करने का हक-दार हो गया है, उसके वेतन में से उसे द्वारा प्राप्त पेशन अथवा गेया उपदान से समतुल्य पेशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अभिदायक या किसी अन्य प्रकार के भेवा-निवृत्ति कायदे, यदि कोई है, को तुल रखने का वर दी जाएगी, परन्तु इनमें से उसके द्वारा प्राप्त व्यवत्रा प्राप्त किए जाने थे भेवा-निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेशन का नहीं की जाएगा।”

3 उक्त नियमों के नियम 6 गे, —

(1) ज्ञ रिगम (1) के खण्ड (1) में “या उभका कोई भग”
—श्राव्य विलोपित कर दिया जाएगे ।

(2) उप नियम (3) में "180" संख्या के स्थान पर "240 संख्या प्रतिस्थापित की जाएगी।

4 उक्त नियमों के नियम 8 के उप-नियम (2) में, “या उमका कोई भाग”—में शब्द विलोपित कर दिया जाएगा।

5 उक्त नियमों पर नियम 15 के बाद निम्नलिखित नियम ओडा जागति, अर्थात् :—

“15-का, उक्ते विषयों के नियम 4 से 15 सक किसी भार के होते हुए भी मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकारियों के अधिना को मेंश रत्न नवा उन्हे उपराज अन्य परिवर्तियों वही होती जो कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (लेख की शर्त) अधिनियम, 1954 (1954 सा 28) और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भर्ते) नियमावली, 1956 ए उच्च न्यायालयों के मेंदारत न्यायाधीशों को प्रनतिवै है।”

[सं. क. 12018/2(iii)/89-प्रश्ना, अधि.]

ध्यारुद्धारात्मक शापन

बंद्रीग सरकार ने मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकारण (प्रधान, उपराष्ट्राधिकारी तथा मरकारों के बेतन तथा भर्ते और सेवा की शर्तें) नियमांकिती, 1986 में संशोधित करने का निर्णय किया है।

2. यह प्रभागित किया जाता है कि इस अधिसूचना का भविष्य लक्षी प्रधाव होगा और इसका मह्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकारण में पहले से ही कार्यरत किसी अन्यथा, उपायकार्य और मरहेंगे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी.—ये मुख्य नियम भारत में राजपत्र में स्तिंशक ६-१२-१५१६
वी.स. का. नि. स १२५३(ई) द्वारा प्रकाशित किए थे।

G.S.R. 1048(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1989.

(2) Save as otherwise expressly provided they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules) for the proviso to rule 3, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st June, 1988, namely :—

"Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a Member of a person who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of

pension and or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him".

3. In rule 6 of the said rules,—

- (1) in clause (i) of sub-rule (1), the words "or a part thereof" shall be omitted;
- (2) in sub-rule (3), for the figures "180", the figures "240" shall be substituted.

4. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (2) the words "or a part thereof" shall be omitted.

5. After rule 15 of the said rules, the following rule shall be inserted namely :—

"15A. Notwithstanding anything contained in rules 4 to 15 of the said rules, the conditions of service and other perquisites available to the Chairman and Vice-Chairman of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956".

[No. A-12018/2(iii)/89-AT]

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Services of Chairman, Vice-Chairman and Members, Rules, 1986.

2. It is certified that this notification would have prospective effect and would not affect any Chairman, Vice-Chairman and Members of the Madhya Pradesh Administrative Tribunal already in position.

Foot Note :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 1253(E) dt. the 5-12-1986 in the Gazette of India.

सा. का. नि. 1049(ग) —केन्द्रीय सरकार प्रशासनिक अधिकरण प्रधिनियम, 1995 (1985 का 13) की शार्त 35 की उपधारा (2) के बाण्ड (ग) के साथ परिवर्त उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके हुए, एक्स्ट्राना कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रध्याय, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के बेतन तथा भग्ने और सेवा की शर्तों) नियमावली 1986 में और आगे मंशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम जनानी है, प्रथम—

1 (1) उन नियमों का नाम कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रध्याय, उपाध्यक्ष और सदस्यों के बेतन तथा भग्ने और सेवा की शर्तों) मंशोधन नियमावली, 1989 है।

(2) ग्रामव्यवस्था स्तर से जैसा मन्यथा उपविधित है, उसके पिछाय नियम मरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होये।

2. कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रध्याय, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के बेतन तथा भग्ने और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1986 (विसे इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा), में नियम 3 के परस्तुक के लिए, निम्नलिखित परस्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा और जून, 1988 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित किया जाएगा, मात्रा जाएगा, प्रत्यात्—

"परन्तु किसी ऐसे व्यक्ति की प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य के लिए में नियमित की स्थिति में जो किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्पष्ट में सेवा-निवृत्त हुआ है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य मरकार के मध्यीन सेवा से निवृत्त हुआ है या जो पेशन और या उपदान, अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अधिदाय या स्पष्ट कर्तव्य के सेवा-निवृत्ति कायदे प्राप्त कर रहा है या कर चुका है या प्राप्त करने का तुकाराम हो गया है, उसके बेतन में से उस के द्वारा प्राप्त पेशन मध्यबा सेवा उपदान के समतुल्य पेशन या अभिदायी भविष्य निधि में नियोजक के अधिदाय या किसी अन्य प्रकार के सेवा-निवृत्ति कायदे, मदि कोई हो, को मूल रूप से कर दी जाएगी, परन्तु इनमें से उसके द्वारा प्राप्त अध्यक्ष प्राप्त किए जाने वाले मेवा-निवृत्ति उपदान के समतुल्य पेशन कम नहीं जी जाएगी।"

3. उक्त नियमों के नियम 6 में—

(1) उप नियम (1) बाण्ड (1) में "या उपका कोई भाग" ---मुख्य विलोपित कर दिए जाएंगे।

(2) उप नियम (3) में "180" मंश्यों के स्थान पर "240" मंश्यों प्रतिस्थापित की जाएंगी।

4. उक्त नियमों के नियम 8 के उपनियम (2) में, "या उतका कोई भाग" ---ये शब्द विलोपित कर दिए जाएंगे।

5. उक्त नियमों के नियम 15 के अ.द निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, प्रत्यात्—

"15-क, उक्त नियमों के नियम 4 से 15 तक किसी बात के होते हुए भी कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण के प्रध्यक्ष की सेवा शर्ते स्थान उक्ते उपलब्ध अन्य परिवर्तियों वही होंगी जो कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्त) प्रधिनियम, 1954 (1954 का 28) और उच्च न्यायालय न्यायाधीश (याकार भर्ते) नियमावली, 1986 में उच्च न्यायालयों के सेवारस न्यायाधीशों को प्रदत्त है।"

[स. क 12018/2(iv)/89-प्रका. प्रधि.]

श्रीमती पी. वी. वल्लाजी कुहटी, अवार सचिव

स्थानात्मक जापन

केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण (प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों के बेतन तथा भग्ने और सेवा की शर्तों) नियमावली, 1986 में मंशोधन करने का नियर्ण किया है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रधिसूचना का प्रतिष्ठान लक्ष्य प्रभाव होता है और इसका कर्नाटक प्रशासनिक अधिकरण में पहले से ही कार्यस्त किसी प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाद टिप्पणी :— ये मुख्य नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 17 सितम्बर, 1986 की स. का. नि. स. 1092(ई) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

G.S.R. 1049(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (c) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government

ment hereby makes the following rules further to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members), Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Karnataka Administrative Tribunal, (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Amendment Rules, 1989.
- (2) Save as otherwise expressly provided they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the said rules), for the proviso to rule 3, the following proviso shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st day of June, 1988, namely :—

“Provided that in the case of an appointment as a Chairman, Vice-Chairman or a Member of a person who has retired as a judge of a High Court or who has retired from service under the Central Government or a State Government and who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension and or gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay shall be reduced by the gross amount of pension equivalent of service gratuity or employer's contribution to Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any, but excluding pension equivalent of retirement gratuity, drawn or to be drawn by him”.

3. In rule 6 of the said rules,—

- (1) in clause (i) of sub-rule (1), the words “or a part thereof” shall be omitted;
- (2) in sub rule (3), for the figures “180”, the figures “240” shall be substituted.

4. In rule 8 of the said rules, in sub-rule (2) the words “or a part thereof” shall be omitted.

5. After rule 15 of the said rules, the following rule shall be inserted, namely :—

“15A. Notwithstanding anything contained in rules 4 to 15 of the said rules, the conditions of service and other perquisites available to the Chairman and Vice-Chairman of the Karnataka Administrative Tribunal shall be the same as admissible to a serving Judge of a High Court as contained in the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954 (28 of 1954) and High Court Judges (Travelling Allowances) Rules, 1956”.

[No. A-12018/2(iv)/89-AT]

Smt. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The Central Government has decided to amend the Karnataka Administrative Tribunal (Salaries and Allowances and Conditions of Service of Chairman, Vice-Chairman and Members) Rules, 1986.

2. It is certified that this notification would have prospective effect and would not affect any Chairman, Vice-Chairman and Members of the Karnataka Administrative Tribunal already in position.

Foot Note :—The Principal rules were published vide No. G.S.R. 1092(E) dated the 17-9-1986 in the Gazette of India.